Dr. K. L. Rao: I must submit that Madhya Pradesh is the largest State in the country, and it is more widespread. For rural electrification, a very close network of the distribution system is necessary, and the distribution lines come in only as part of the development of the country, generally industry.

I am sorry I have been misunderstood in respect of an earlier answer that I had given. What I said was this. In the case of the State of Madhya Pradesh, the number of villages is very large, being of the order of about 70,000. Therefore, we have got to study very carefully which villages must be electrified, and how that should be done.

Shri Ranga: He will go on studying.

1965-66 के बजट में की गई कटौतियां

+

*744. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाकिस्तानी आक्रमण के कारण 1965-66 के बजट में क्या क्या कटौतियां की गई; और

(ख) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य उपक्रमों में की गई बचत दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें 1965-66 के बजट में मंत्रालयों के अनुसार की गई बचत दिखाई गई है। [पुस्तकालय में रखा-देखिये संख्या एल० टी०—5878/66]

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय जो विवरण आपने सदन् पटल पर रखा है तो उस में मैंने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य उपक्रमों में की गई बचत के बारे में पूछा था लेकिन उसे देखने से मालूम होता है कि उसमें आपने रेलवेज़ के बारे में और पबलिक अंडरटेकिंग्स के बारे में सूचना नहीं दी है और मंत्री महोदय जो इस तरह से जवाब भी पूरा नहीं देते हैं तो इस के लिए आप ज़रा उन्हें आवश्यक आदेश दें। रेलवेज़ में क्या कटौती की गई है इसका कोई ज़िक्र नहीं है तो रेलवेज़ भी तो एक मिनिस्टरी ही है।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें रेलवेज़ और पबलिक अंडरटेकिंग्स के बारे में सूचना नहीं है। इतने दिनों के भीतर जितनी भी हम सूचना एकत्र कर सके हैं वह हम ने यहां इस विवरण में रख दी है बाक़ी सूचना इकट्ठी हो जाने पर उसे भी हम रखने की कोशिश करेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप ने जो विवरण सदन् पटल में रखा है उस के अनुसार करीब 61 करोड़ रुपये की बचत हुई है जोकि विभिन्न प्रकार की कटौतियां करने से सम्भव हो सकी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या और अधिक प्रयास करने से इससे अधिक बचत नहीं हो सकती थी और इस 61 करोड़ रुपये का उपयोग किस प्रकार से किया गया ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरा तो ख़याल था कि माननीय सदस्य को संतोष होगा। वैसे तो इस से पहले भी प्रयास हुआ था पिछले साल भी हुआ था लेकिन इस साल पहले की अपेक्षा अधिक बचत की जा सकी है और यह जो इस बार अधिक रुपये की बचत की जा सकी है तो उस प्रयास में इसलिए हमें सफलता मिली है कि सभी मंत्रालयों ने

इस में हमें सहयोग दिया है । इस का प्राधार यह है कि हमारे पुराने प्रधान मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि नौन प्लांड ऐक्सपेंडीचर में 10–15 प्रतिशत: की कटौती होनी चाहिए उसी के मुताबिक इस बजट में कटौती करने की कोशिश की गई है जोकि 61 करोड़ के करीब है । माननीय सदस्य को ख़याल होगा कि पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि 48 करोड़ की कटौती हुई है तो उससे यह 12–13 करोड़ बेशी हुई है । इसलिए यह बचत करने की कोशिश लगातार चलती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा बचत करने की हम कशिश करेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने यह पूछा था कि यह जो 61 करोड़ रुपये की बचत की गई है इसे किस मद में खर्च किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक बचत को खर्च करने का सवाल है तो उसे योजना पर खर्च करना है प्लांड रिसोर्सिज में जहां भी कमी होगी वहां पर खर्च किया जायगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या डिफेंस में खर्च किया जायगा ?

Shri P. C. Borooah: At a time when we are facing a serious foreign exchange crises, our imports of miscellaneous consumers goods including luxuery goods, amounted to Rs. 65 crores in 1965, an increase of Rs. 4 crores over 1964. Does this signify that we are not making any serious attempt at cutting down expenditure?

Shri L. N. Mishra: We are making serious efforts at cutting down expenditure; I was referring to the civil expenditure by different Ministries, not the foreign exchange part of it.

श्री भागवत झा आजाद : जहां एक तरफ़ सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो और इस के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय हर वर्ष अधिक से अधिक अपना उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं वहां इस विवरण के अनुसार सिंचाई और बिजली मंत्रालय में 160 लाख की कटौती की गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि का क्या यही उपाय है कि सिंचाई और बिजली मंत्रालय में कमी की जाय या यह कि उसे और बढ़ाया जाय ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम ने प्रोजेक्ट्स या प्लांड ऐक्सपेंडीचर में कटौती नहीं की है कटौती हम ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड में की है । जैसे कि कहीं डुप्लीकेशन है तो वहां कटौती कर दी है या जहां 1, 2 कारपोरेशंस हैं वहां एक कारपोरेशन बना दी है यानी डुप्लीकेशन को रोकने और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्सपेंसेज में हम ने कटौती की है बाक़ी प्रोजेक्ट्स का खर्चा हम ने नहीं घटाया है ।

Shri Subodh Hansda: I find from the statement that the cut in the Ministry of Education is Rs. 487.90 lakhs. There is a countrywide agitation of school and college-teachers.

Do Government now propose to restore this cut just to meet their demands?

Shri L. N. Mishra: I do not think the number of teachers is going to be reduced. Whatever we have done has been done with the consent of the Ministries concerned. I do not think teachers are going to be affected. It must be in relation to administrative expenditure.

Shri S. C. Samanta: The biggest cut is in the Department of Transport, Shipping and Tourism. May I know whether this Department was also helping the Defence Department?

Shri L. N. Mishra: Transport and shipping of course, help in national defence. I do not think Defence is going to suffer as a result of these cuts.

Shrimati Savitri Nigam: What are the items of these cuts, and has any effort been made to reduce the army of advisers, joint secretaries, secre-

taries, under-Secretaries and staff cars which are increasing day by day?

Shri L. N. Mishra: The basis is this, that the Ministry of Finance, Department of Expenditure, sent a note to all the ministries concerned, appealing to them to co-operate in this drive for economy, and they co-operated. So far as this saving is concerned, it is in the administrative expenditure; we are attempting to cut administrative expenditure.

श्री यशपाल सिंह : अगर सरकार कल्चरल प्रोग्राम्स का तमाम रुपया रोक कर डेवेलपमेंट के कामों में लगाये तो क्या नुकसान हो जायेगा ? क्या सरकार इस के ऊपर विचार कर रही है कि नाचने, गाने के खर्च को मौजूदा टाइम देख कर फौरन बन्द किया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे ख़याल से जीवन के लिए नाचना, गाना आदि मनोरंजन के साधन भी एक आवश्यक चीज़ है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या काम आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों के लिए भले ही कोई काम न आये लेकिन औरों के लिए आ सकता है ।

श्री रामेश्वरानन्द: औरों के काम भी क्या आयेगा और आपके काम भी क्या आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे तो काम नहीं ही आयेगा, मुझे तो आप को अपने साथ साधू के वेष में ले चलना चाहिए ।

Shri Indrajit Gupta: From the statement which has been laid on the Table of the House, it appears that out of Rs. 61 crores of total saving, about Rs. 21 crores, or one-third of the total, is on account of one department alone, that is the Department of Transport, Shipping and Tourism. May I know whether this is due to the fact that there was unusually heavy extravagance in this department and greater scope for reduction, or it is because the other ministries are not yet willing to make commensurate economies?

Shri L. N. Mishra: I would not like to express any opinion. I would only pay my compliment to that Ministry that they have co-operated very well.

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether this cut that has been effected is on an *ad hoc* basis or some selected departments have been taken where this cut has been effected on the principle that the actual working of projects is not retarded?

Shri L. N. Mishra: This is not an *ad hoc* cut. Proper studies have been made, ministries have studied it, and it has been done as a result of proper study and examination. I do not think any project is going to suffer on account of this.

Shri Ranga: What was suggested by the Opposition, and also some members from the Congress side, and what was accepted by the previous Finance Minister was an economy cut of 10 to 15 per cent instead of what my hon. friend seems to indicate has been achieved. It was not said that it should be restricted to only non-plan expenditure. May I know whether the Finance Minister wants to resile from that position and wishes to restrict this economy drive only to non-plan expenditure, and not to plan expenditure at all, and whether there would not be any economy cut?

Shri L. N. Mishra

Shri Ranga: Let the senior Minister answer. Why are you in a hurry?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhri): I shall answer the question. The cut will be made wherever the cut can be borne, wherever it is most useful; whether it is plan or non-plan, that matter will have to be taken into consideration. What is to be done is to realise that there has to be economy, and wherever economy can be made economy will be made.

Shri Ranga: That takes us nowhere. What is that answer? It is a mere ceremonial answer? Is it a specific answer to my question? What is the policy of the Government? Have they no policy? Are they going to consider it? Let them say so?

Shri Sachindra Chaudhuri: The policy is to economise wherever economy is possible.

Shri Ranga: What is it that he said?

Mr. Speaker: The policy is to economise wherever economy is possible.

Shri Ranga: Therefore, there is to be no general drive for economy at all. Is that what we have to understand? We know now where we are going to stand.

Shri Sachindra Chaudhuri: I can only give the answer, I cannot give understanding.

Shri Ranga: Therefore, he goes back. (*Interruptions*). Do not go on yawning. You will be yawning when the taxes come upon your heads.

Shri Hem Barua: If the Finance Minister says like that, that he can give the answer but he cannot give understanding, is it not a reflection on the Member concerned? According to the rules, we are here to elicit information, and the Minister has to supply the information.

Shri Ranga: He has the cheek to say like that.

Shri Hem Barua: Here is a Minister who is behaving in a very haughty manner.

Shri Ranga: He is the Finance Minister too.

Mr. Speaker: I have said so many times that we ought to use restrained language.

Shri Ranga: You give that sermon only to us.... (*Interruptions*). When he used that language you could have told him; we expected that from the Chair.

Mr. Speaker: Am I addressing the hon. Member now? If the hon. Minister has said it, I am addressing the Minister, and not Prof. Ranga.

Shri Ranga: If my hon. friend did not take the trouble of raising that objection?

Mr. Speaker: If it is taken in a sportsmanlike spirit, why should I take it up? Unless objection is raised, I would not have interferred in that, if the Members take it in a sportmanlike spirit.

Shri Ranga: That is my complaint because the Chair is expected to be vigilant not only in regard to the Opposition but also in regard to what the Minister says.... (*Interruptions*). They will get what they deserve at this rate.

Shri Kapur Singh: Do not rules require that no insinuations are to be made during the proceedings of this House? Has not the hon. Minister made a broad insinuation that my leader is devoid of understanding?

Mr. Speaker: I do not think they should feel so hurt.

Shri Hem Barua: But can he supply understanding?

श्री सरजू पाण्डेय : इस स्टेटमेंट को देखने से मालूम होता है कि और मंत्रालयों के मुकाबले में सब से कम कटौती कम्यूनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट में हुई है जब कि सब से ज्यादा फ़िजूलखर्ची इस विभाग में होती है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार ब्लाकों की जीपों को छीन लेने के बारे में कोई विचार कर रही है या नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : ब्लाकों की जीपों के बारे में मैं इस समय नहीं कह सकता हूं । माननीय सदस्य श्री भागवत झा आज़ाद ने कहा है कि कृषि और सिंचाई पर ज्यादा ख़र्च होना चाहिए । मेरे ख़याल से कम्यूनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट के ख़र्च में जो कटौती की गई है वह एडमिनिस्ट्रेशन के ख़र्च में की गई है । अगर उस में और कटौती करने

की गुंजायश होगी, तो हम और कटौती करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन—डा० सिंघवी ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को हर एक सवाल में तो मौका नहीं दे सकता हूं । उन का नाम तो कहीं होता नहीं है । जिन माननीय सदस्यों का नाम होता है मुझे उन को भी बुलाना होता है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय जिन सदस्यों के नाम होते हैं उन को भी नहीं बुलाया जाता है । इस प्रश्न पर हम लोगों में से पांच सदस्यों के नाम थे, लेकिन एक को भी नहीं बुलाया गया । अगर नाम रहे, तो भी नहीं बुलाया जाता है और अगर नाम न रहे, तब भी नहीं बुलाया जाता है ।

P. L. 480

+

***745. Dr. L. M. Singhvi:**
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri Maheswar Naik:
Shri Indrajit Gupta:
Shri P. C. Borooah:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Madhu Limaye:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total freight charges for PL 480 imports in terms of the foreign exchange during the current year;

(b) whether these charges are considered to be on the high side; and

(c) how it is proposed to meet these charges?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The total freight charges for PL 480 imports, paid for in foreign exchange during the current financial year, are estimated at Rs. 36 crores.

(b) The vessels are chartered in the open market at the best available terms.

(c) These charges have to be met from our free foreign exchange resources.

Dr. L. M. Singhvi: May I know whether the hon. Finance Minister has specifically evaluated the steady mounting bill for freight in terms of foreign exchange and whether it is the conclusion of the government that these imports have ceased to confer the benefits that were intended to be conferred on our country in view of the large exchange implications to be paid for the freight charges?

Shri Sachindra Chaudhuri: So far as freight charges are concerned I have given the estimated figures for the year 1965-66. We have got to import large quantities of food in the next year and the charges would be higher. We take into consideration that fact and see what would be of benefit to us. I would like to tell this House through you that there has been full consideration given to the benefit which is received by getting these foreign imports which are mostly food and a certain quantity of cotton. It is felt that even at the expense of the freight involved in foreign exchange it is worthwhile importing these goods.

Dr. L. M. Singhvi: Has the government taken up the matter with the US government that the payment of freight charges in foreign exchange has coincided with the developing crisis of foreign exchange in our country and if they wished to be helpful it would be far better for them to waive this condition for a few more years? Has this been taken up and, if so, with what result?

Shri Sachindra Chaudhuri: This is a matter which is always under consideration and it has been discussed as far as discussion is possible. It